

CS (MAIN) EXAM, 2010

Serial No.

1906

B-DTN-K-QBB

PUBLIC ADMINISTRATION

Paper—II

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 300

INSTRUCTIONS

Each question is printed both in Hindi and in English.

Answers must be written in the medium specified in the Admission Certificate issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer-book in the space provided for the purpose. No marks will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Certificate.

Candidates should attempt Questions 1 and 5 which are compulsory, and any three of the remaining questions selecting at least one question from each Section.

The number of marks carried by each question is indicated at the end of the question.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है ।

SECTION—A

1. Attempt the following in not more than 200 words each :— 3×20=60
 - (a) “The rule of kings depends primarily on written orders” Why did Kautilya favour Codification of Laws ?
 - (b) Is it correct to state that “one of the major reasons for the failure of many public sector undertakings was due to departures from the original concept of autonomy” ?
 - (c) Does the emergence of an Empowered Group of Ministers at the Central level impair the doctrine of Cabinet responsibility ?
2. (a) It is said that the British made a significant contribution towards modernising the Indian Administrative System on a ‘rational-legal’ basis. Justify the assessment with reference to the period from 1830 to 1865. 30
- (b) Comment on the following statements :— 30
 - (i) “The more developed an administrative system became the greater the likelihood that it would have developmental effects.”

खंड—'क'

1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, जो प्रत्येक 200 से अधिक शब्दों में नहीं होने चाहिए :— 3×20=60

(क) "नरेशों का शासन मुख्यतः लिखित आदेशों पर निर्भर करता है'' क्या कारण था कि कौटिल्य कानूनों के संहिताकरण के पक्ष में था ?

(ख) क्या यह कहना सही होगा कि "अनेक सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक कारण स्वायत्तता की मूल संकल्पना से हट जाना था ?''

(ग) क्या केन्द्रीय स्तर पर मंत्रियों के सशक्तीकृत समूह का उदय मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत को क्षति पहुँचाएगा ?

2. (क) कहा जाता है कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र के, युक्तिसंगत-वैधिक आधार पर, आधुनिकीकरण की दिशा में अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1830 से 1865 के बीच की अवधि के संदर्भ में, इस आकलन को सही साबित कीजिए। 30

(ख) निम्नलिखित कथनों पर टिप्पणी कीजिए :— 30

(i) "प्रशासनिक तंत्र जितना अधिक विकसित हो जाएगा, उतनी ही बड़ी संभावना होगी कि उसके विकासात्मक प्रभाव होंगे।''

- (ii) "The thrust of development administration failed to energise the Indian bureaucracy."
3. (a) With reference to India, discuss the assertion that administrative reforms are multi-dimensional and need to be substantiated by reforms in other related areas of state action. 30
- (b) The prevalence of multiple channels for transfer of resources from the Centre to the States is stated to have compounded the problems of federal fiscal arrangements. Discuss. 30
4. (a) "In an era of hung parliaments the power of the President expands, more so when the incumbent decides to be assertive." Comment on the statement with reference to the situation in India during the last two decades. 30
- (b) "..... Judges and Courts have creatively reinterpreted their statutory authority and expanded their own power and enhanced their standing vis-a-vis the legislature and executive." Critically examine this assessment. 30

(ii) "विकास प्रशासन का प्रणोद भारत के अधिकारीतंत्र में शक्ति का संचार करने में विफल रहा।"

3. (क) भारत के संदर्भ में इस दृढ़कथन पर चर्चा कीजिए कि प्रशासनिक सुधार बहु-आयामी होते हैं और राज्य कार्य के अन्य संबंधित क्षेत्रों में सुधारों के द्वारा उनको पुष्ट करने की आवश्यकता होती है। 30

(ख) कहा जाता है कि केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण के लिए अनेक सरणियों के प्रचलन ने परिसंघीय राजकोषीय व्यवस्थाओं की समस्याओं में वृद्धि कर दी है। इस पर चर्चा कीजिए। 30

4. (क) "त्रिशंकु संसदों के युग में, राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार हो जाता है, ऐसा और भी अधिक जब पदधारी आग्रही होने का निर्णय लेता है।" पिछले दो दशकों के दौरान भारत में स्थिति के संदर्भ में, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। 30

(ख) "..... न्यायाधीशों और न्यायालयों ने अपने कानूनी प्राधिकार का सर्जनात्मक रूप से पुनः निर्वचन किया है, अपनी स्वयं की शक्ति का विस्तार किया है और विधान-मंडल और कार्यपालिका के मुकाबले में अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की है।" इस आकलन का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। 30

SECTION—B

5. Comment on any **THREE** of the following in not more than 200 words each :— 3×20=60

(a) "Public Interest Litigation (PIL) has undergone several changes since its inception in 1980s."

(b) "Civil service neutrality is a fiction. How any thinking person can be neutral?"

(c) States with a record of good governance, it is argued by spokespersons of some states, lost their earlier share from the Finance Commission's award.

6. (a) Explain the context and perspectives of the following statements :— 30

(i) The Planning Commission is "an armchair adviser".

(ii) The Planning Commission should reinvent itself as a systems reforms commission in the backdrop of changed global and domestic scenarios.

खंड—'ख'

5. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए, जो प्रत्येक 200 से अधिक शब्दों में न हो :— 3×20=60

(क) "लोक हित मुकदमेबाज़ी (पी.आई.एल.) में, 1980 के दशक में उसके प्रारंभ से, अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं।"

(ख) "सिविल सेवा तटस्थता एक कल्पना है। कोई भी विचारशील व्यक्ति तटस्थ कैसे हो सकता है?"

(ग) कुछ राज्यों के प्रवक्ताओं के द्वारा दलील दी जाती है कि उत्तम शासन के रिकार्ड वाले राज्य वित्त आयोग के पंचाट के द्वारा अपने पहले के अंश से वंचित हो गए हैं।

6. (क) निम्नलिखित कथनों के संदर्भों एवं संदर्शों को स्पष्ट कीजिए :— 30

(i) योजना आयोग "एक अव्यावहारिक (आर्मचेयर) सलाहकार" है।

(ii) परिवर्तित वैश्विक और देशीय परिदृश्यों की पृष्ठभूमि में, योजना आयोग को तंत्र सुधार आयोग के रूप में अपना पुनराविष्कार करना चाहिए।

- (b) The Second Administrative Reforms Commission, in its 10th Report, observes that “the common perception is that the incentive structure in government is too weak and inadequate to motivate better performance.” Elucidate. 30

7. Comment on each of the following in not more than 200 words each :— 3×20=60

- (a) “Non-Governmental Organisations play a catalytic role in enabling communities to define their own priorities.....”
- (b) The optimism expressed by the proponents of the Financial Responsibility and Budget Management Act, 2003, in ensuring fiscal discipline appears to be unwarranted.
- (c) “The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNURM) is one of the biggest reforms-linked development programmes taken up by the Government.”
8. (a) It is argued that the Bhopal gas disaster and the response pattern to it reflect multiple vulnerabilities relating to systems of corporate social responsibility, governance at local, state and central levels, and legal safeguards and liabilities.

Comment on this assessment. 30

(ख) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 10वीं रिपोर्ट में, टिप्पणी की है कि "सामान्य बोध है कि सरकार में प्रोत्साहन संरचना इतनी अधिक कमजोर और अपर्याप्त है कि वह बेहतर निष्पादन के लिए अभिप्रेरित नहीं कर सकती।" इसको सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 30

7. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर टिप्पणी कीजिए, जो प्रत्येक 200 से अधिक शब्दों में न हो :— 3×20=60

(क) "समुदायों को अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने में सक्षम बनाने में गैर-सरकारी संगठन एक उत्प्रेरकी भूमिका का निर्वहन करते हैं :—"

(ख) राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करने में, वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रस्तावकों द्वारा व्यक्त आशावाद अनुचित प्रतीत होता है।

(ग) "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन (जे.एन.यू.आर.एम.) सरकार द्वारा हाथ में लिए गए बृहत्तम सुधार-संयोजित विकास कार्यक्रमों में से एक है।"

8. (क) तर्क दिया जाता है कि भोपाल गैस आपदा और उसके प्रति अनुक्रिया प्ररूप, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, स्थानीय, राज्यीय एवं केन्द्रीय स्तरों पर शासन, और विधिक रक्षोपायों एवं दायित्वों के तंत्रों से संबंधित बहु-सुभेद्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

इस आकलन पर टिप्पणी कीजिए।

30

- (b) With the creation of new regulatory agencies in the wake of liberalisation, overlapping jurisdictions and conflicts became the new trend. Is there need for the creation of a super-regulator or unified regulator ?

30

(ख) उदारीकरण के परिणामस्वरूप नव-विनियामक एजेंसियों की रचना के साथ अतिव्यापी अधिकारिताएं और टकराव एक नई प्रवृत्ति बन गई। क्या किसी एक सुपर-विनियामक या एकीकृत विनियामक के निर्माण की आवश्यकता है ?

30

Serial No.

B-DTN-K-QBB

लोक प्रशासन

प्रश्न-पत्र—II

समय : तीन घण्टे

पूर्णांक : 300

अनुदेश

प्रत्येक प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तक के मुखपृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक प्रश्न के अंत में दिए गए हैं।

Note : English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.